

न्यूज़ हुडे

केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के लिए ओडिशा सरकार के अध्यादेश का विरोध किया है

- लिंगराज मंदिर और इससे संबद्ध आठ मंदिरों के अनुष्ठानों और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए ओडिशा सरकार ने "लिंगराज मंदिर अध्यादेश, 2020" जारी किया था।
- गृह मंत्रालय का कहना है कि इस अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार संरक्षित 12 स्मारकों और लिंगराज मंदिर सहित तीन तालाबों को भी अपने दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए, यह ओडिशा विधानमंडल की विधायी शक्ति से बाहर है। साथ ही, यह अध्यादेश प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष कानून, 1958 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है।
 - इस अध्यादेश में प्राचीन भवनों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण का भी प्रावधान है, जबकि केंद्र ने तर्क दिया है कि निर्माण की अनुमति केवल राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है।
- लिंगराज मंदिर: भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण राजा ययाति केशरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। 11वीं शताब्दी में राजा लालतेंदु केशरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था।
 - इस मंदिर का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। यह कलिंग शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
 - यह मंदिर चार खंडों में विभाजित है—
 - गर्भगृह (मुख्य मूर्ति स्थल),
 - यज्ञ शाला (प्रार्थना के लिए कक्ष),
 - भोग मंडप (अर्पण के लिए कक्ष) और
 - नाट्य शाला (नृत्य के लिए कक्ष)

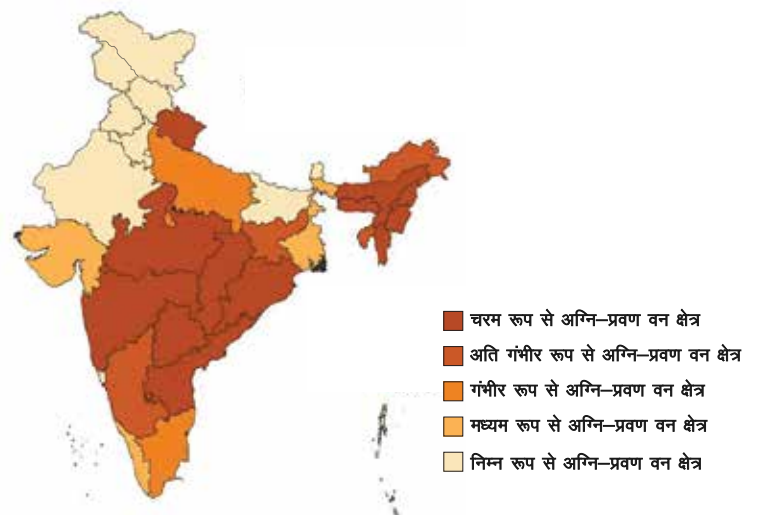


प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष कानून, 1958 {Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958}

➤ यह कानून प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है।

एक अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में वनाग्नि की घटनाओं और तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है

- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) ने 'मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन चेंजिंग क्लाइमेट' नाम से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है।
- अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
 - देश के 75% से अधिक भारतीय जिले चरम जलवायु संबंधी घटनाओं वाले हॉटस्पॉट हैं। वहीं 30% जिले चरम वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट हैं।
 - पिछले दो दशकों में वनाग्नि की घटनाओं में 10 गुना वृद्धि हुई है।
 - ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) देशों में भारत वनाग्नि के संदर्भ में दूसरा सबसे सुभेद्य देश है।
 - पिछले दो दशकों के दौरान मिजोरम में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
 - वनाग्नि के मामले में 89% चरम हॉटस्पॉट जिले मुख्यतः सूखे से ग्रसित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थित हैं।
 - तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र उच्च तीव्रता वाली वनाग्नि की घटनाओं के लिए सर्वाधिक संवेदनशील राज्य हैं।
 - हाल ही में, राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग बेमौसम थी। साथ ही, उच्च तापमान के कारण आग और तेजी से फैल गयी।



○ प्रमुख सिफारिशें

- वनाग्नि को आपदा के एक प्रकार के रूप में मान्यता देने की जरूरत है। साथ ही, इसे राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा प्रबंधन योजनाओं में एकीकृत करने की भी आवश्यकता है।
- वनाग्नि से संबंधित एक चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। यह रियल टाइम प्रभाव आधारित चेतावनी जारी करेगा।
- अनुकूलन क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।
- स्वच्छ वायु से युक्त आश्रय स्थल बनाए जाने चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से निलंबित किया

- महासभा ने रूस द्वारा यूक्रेन के साथ युद्ध करने के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने हेतु एक संकल्प स्वीकार किया है।
 - महासभा, मानवाधिकार परिषद के किसी सदस्य की 'परिषद में सदस्यता के अधिकारों' को निलंबित कर सकती है। ऐसा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से किया सकता है।
 - अनुपस्थित सदस्यों की गणना नहीं की जाती है। किसी संकल्प को पारित होने के लिए दो-तिहाई हाँ/ना (Yes/No) मतों की आवश्यकता होती है।
 - रूस से पहले, लीबिया इस परिषद से निलंबित होने वाला अंतिम सदस्य देश था। लीबिया को वर्ष 2011 में निलंबित कर दिया गया था।
- भारत संकल्प पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा।
- इस निर्णय के संभावित प्रभाव
 - यह एक और मजबूत व संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है। यह रूस एवं उसका साथ देने वाले देशों या तटस्थ देशों पर दबाव बढ़ाएगी।
 - इससे विश्व में गुटबंदी के और बढ़ने का खतरा है। इससे संघर्षों में वृद्धि हो सकती है तथा शांति प्रयास बाधित हो सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह संगठन विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है।
 - इसके सदस्यों की संख्या 47 है। इसके सदस्यों का चुनाव महासभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
 - इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2006 में किया था। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है।

चीन ने लद्दाख में तीन बार "पावर ग्रिड सिस्टम्स" को हैक करने का प्रयास किया

- हैकर्स द्वारा शैडोपैड (ShadowPad) नामक ट्रोजन का इस्तेमाल "स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स (SLDCs)" को हैक करने के लिए किया गया। हालांकि, भारत में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर (यानी महत्वपूर्ण अवसंरचना) के लिए पहले से मौजूद सुरक्षा उपायों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। कथित तौर पर यह माना जाता है कि शैडोपैड ट्रोजन को चीन की सरकार द्वारा बनाया गया है।
 - स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स: ये रियल टाइम आधार पर ग्रिड कंट्रोल और इलेक्ट्रिक डिस्पैच के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स (CI): इसका आशय देश के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक भौतिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी फैसिलिटी (या प्रतिष्ठान / केंद्र), नेटवर्क, सेवाओं और परिसंपत्तियों से है। इनमें किसी भी प्रकार का व्यवधान होने से स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक या सामाजिक कल्याण या सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- भारत में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय:
 - नीतिगत उपाय: उनकी सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति घोषित की गयी थी। इसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिए एक सुरक्षित और लचीले (रेजिलिएंट) साइबर स्पेस का निर्माण करना है।
 - संस्थागत उपाय:
 - राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre: NCIIIPC): इसकी स्थापना देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CIs) को विनियमित और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए की गयी है।
 - भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (Indian Computer Emergency Response Team: CERT-IN): यह कंप्यूटर सुरक्षा और उन पर हमलों से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
 - राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (National Cyber Security Coordinator: NCSC): इसका कार्य साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग एजेंसियों के साथ समन्वय करना है।
- अन्य प्रमुख पहलें: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत क्षेत्र की सभी यूटिलिटीज (यानी बिजली कंपनी या बिजली केंद्र/प्रतिष्ठान) के लिए साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- इसके अलावा, विद्युत अवसंरचना को बाधित करने के प्रयासों को विफल करने के लिए फायरवॉल और एक विशेष कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल (Computer Security Incident Response Team: CSIRT) बनाने की योजना बनाई गयी है।



यूक्रेन-रूस संकट पर भारत का पक्ष

- भारत ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए शांति, संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। साथ ही, भारत ने संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए रचनात्मक वार्ता का भी समर्थन किया है।
- जनवरी 2022 से, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रक्रियात्मक वोटों और प्रारूप संकल्पों पर मतदान से अनुपस्थित रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स (DBUs) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का लक्ष्य भारत में बैंकिंग के डिजिटल तरीकों के प्रसार को बढ़ाना है।
- RBI के इन दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:
 - डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य का पूर्व अनुभव रखने वाले सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को DBUs खोलने की अनुमति दी गयी है। हालांकि, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को अनुमति नहीं दी गई है।
 - डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में निम्नलिखित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी:
 - खाता खोलना,
 - नकद निकासी और जमा,
 - KYC अपडेशन,
 - ऋण तथा
 - शिकायत दर्ज करना।
 - प्रत्येक DBU को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा।
 - SCBs को प्रत्येक DBU के लिए अलग परिसर (शाखा केंद्र) की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें DBU परिसर में ग्राहकों के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं को मूल बैंक शाखा से अलग रखना होगा।
 - बैंकों द्वारा DBUs की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाएंगे।
 - इसके लिए एक ऐसा डिजिटल तंत्र बनाना होगा, जो रियल टाइम में ग्राहकों की सहायता करे। इससे DBUs के कामकाज, व्यवसाय और सेवाओं से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों का रियल टाइम आधार पर समाधान हो सकेगा।
- डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का महत्व:
 - ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मददगार सिद्ध होंगे। साथ ही, ये इंटरऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देंगे।
 - इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
 - चूंकि, इनके चलते भवन/इमारतों में कार्यरत बैंक शाखाओं की संख्या कम होगी, अतः ये फिजिकल फुटप्रिंट को भी कम करने में सहायक होंगे।
 - बैंकों की नई शाखा खोलने की तुलना में DBUs स्थापित करना सस्ता है। इनके कामकाज, व्यवसाय व संचालन के लिए कम कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। साथ ही, तकनीकी उपकरणों की वजह से इनके रखरखाव में भी कम व्यय होता है। इससे इनके मूल बैंक को प्रति यूनिट अधिक लाभ हो सकता है।

- DBUs एक विशेष फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट/हब के समान होते हैं। इनकी स्थापना के लिए न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता होती है। ये ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी बैंकिंग सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, ये डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का वितरण भी करते हैं।
- केंद्रीय बजट 2022-23 में, सरकार ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की थी।

अन्य सुर्खियाँ

 दूर ऑफ़ ड्यूटी योजना (ToD)	○ सैन्य मामलों के विभाग ने ToD योजना को अंतिम रूप दे दिया है। ○ इस योजना के तहत युवाओं को केवल तीन से पांच वर्ष के लिए सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। ➢ इसका उद्देश्य वेतन और पेंशन पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करना है। यह व्यय सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। ➢ सर्वप्रथम, इस योजना का विचार दिवंगत चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत ने रखा था। ➢ ToD योजना को "अग्निपथ" भर्ती योजना का नाम दिए जाने की संभावना है। सर्वप्रथम, योजना को प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ करने की बात की जा रही है।
 भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी योजना का समर्थन करेगा	○ भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IAE) द्वारा 120 मिलियन बैरल कुल तेल स्टॉक जारी करने की घोषणा का स्वागत किया है। ➢ कच्चे तेल के भंडार को जारी करने का उद्देश्य दुनिया भर में ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। ○ IEA ने अनुमान लगाया है कि विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक रूस को अपने तेल निर्यात में प्रतिदिन लगभग 30 लाख बैरल की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। ○ IEA वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, आयल मार्केट रिपोर्ट आदि का प्रकाशन करती है। ➢ वर्ष 2017 में, भारत एक सहयोगी सदस्य के रूप में IEA में शामिल हुआ था।
 जीरो कूपन बॉण्ड	○ हाल ही में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (IDF) को जीरो कूपन बॉण्ड जारी करने की अनुमति प्रदान करेगा। ➢ यह कर-कुशल (tax-efficient) तरीके से संसाधनों को जुटाने में मदद करेगा। ○ एक जीरो-कूपन बॉण्ड एक ऋण प्रतिभूति प्रपत्र होता है। इन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। ○ इनका बहुत अधिक छूट पर व्यापार किया जाता है। यह परिपक्वता अवधि पर पूर्ण अंकित मूल्य के बराबर लाभ प्रदान करता है। जीरो-कूपन बॉण्ड के खरीद मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर निवेशक के प्रतिफल को दर्शाता है। ○ इसका मूल्य ब्याज दरों में होने वाली वृद्धि से व्युत्क्रमानुपाती (inversely) रूप से संबंधित है।
 नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (NFCT)	○ गूगल पे ने एक नया फीचर 'टैप टू पे फॉर यूपीआई' लॉन्च किया है, जो NFCT का उपयोग करता है। ○ NFC एक अल्प दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है। यह NFC-सक्षम उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार करने और सिंगल टच के साथ सूचना को शीघ्र एवं आसानी से प्रेषित करने में सक्षम बनाती है। ➢ NFC दो उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए विद्युत चुम्बकीय रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से डेटा प्रसारित करता है। ➢ डेटा ट्रांसफर के लिए NFC-सक्षम उपकरणों द्वारा एक-दूसरे को या तो भौतिक रूप से टच करना चाहिए या वे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए। ➢ नोकिया ने वर्ष 2007 में पहला NFC-सक्षम फोन लॉन्च किया था।
 भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम [Indian Sars-CoV-2 Genomic Consortium (INSACOG)]	○ लक्षणान्तरक कोविड-19 के मामलों में गिरावट आने लगी है। इस संदर्भ में INSACOG ने सार्स-कोव-2 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 55 स्थानों पर सीवेज के जल के नमूनों की निगरानी का कार्य आरम्भ कर दिया है। ○ INSACOG वर्ष 2020 में स्थापित 38 प्रयोगशालाओं का एक संघ है। यह भारतीय रोगियों से सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स वेरिएंट का आकलन करता है। ○ इसे संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा स्थापित किया गया है। ○ यह नैदानिक/महामारी विज्ञान डेटा के साथ संपूर्ण जीनोमिक्स अनुक्रमण (WGS) डेटा को सह-संबंधित करने में मदद करता है। इससे लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए अग्रिम तैयारी में सहायता मिलती है।
 इंडियन टेंट टर्टल	○ भारत में इंडियन टेंट टर्टल (पंगशुरा टेंटोरिया) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची- I में दर्ज प्रजाति है। ➢ अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN): लीस्ट कंसर्न। ➢ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES): परिशिष्ट-2. ○ यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश का स्थानिक जीव है। यह ताजे जल की नदियों, दलदलों एवं तालाबों में पाया जाता है। ○ भारत में इसके सामान्य पर्यावासों में शामिल हैं— ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मध्यप्रदेश आदि। उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी। ○ ये कुशल तैराक और मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं।
 विषयों के आधार पर क्वाकवरेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022	○ इसमें 5 व्यापक विषय क्षेत्रों के तहत कुल 51 विषयों को शामिल किया गया है। इसमें भारत के 16 उच्चतर शिक्षा संस्थानों (35 कार्यक्रमों के साथ) को उनकी विषय श्रेणियों में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। ○ भारतीय संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले दो कार्यक्रम हैं: ➢ सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को अपने दंत चिकित्सा कार्यक्रम के लिए 18वां स्थान दिया गया है। ➢ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (ISM) विश्वविद्यालय, धनबाद को अपने मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए 26वां स्थान दिया गया है। ○ QS, विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन पर सबसे लोकप्रिय तुलनात्मक डेटा प्रदान करता है। साथ ही, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (2004 में शुरू) के साथ उच्चतर शिक्षा सेवाओं, प्रदर्शन, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि का एक प्रमुख प्रदाता भी है।



विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल को वार्षिक विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया। इसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और लोगों के विशेष स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया गया है।
- थीम: 'आवर प्लेनेट, आवर हेल्थ'।
- यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को एक स्वतंत्र अंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के रूप में की गई थी।



सुर्खियों में रहे स्थल

बुर्किना फासो (राजधानी: ओगाडोगू)

- बुर्किना फासो की एक सैन्य अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- राजनीतिक सीमाएं:
 - यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है।
 - पड़ोसी देश: माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट।
- भौगोलिक विशेषताएं:
 - सवाना पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है।
 - जलवायु: धूप युक्त, गर्म, शुष्क और धूल भरी।
 - सबसे लंबी नदी: ब्लैक वोल्टा।
 - प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इसमें सोना, मैंगनीज, चूना पत्थर आदि शामिल हैं।



8468022022, 9019066066

www.visionias.in

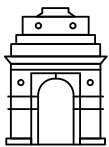


/c/VisionIASdelhi

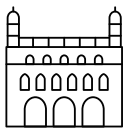
/Vision_IAS

/visionias_upsc

/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



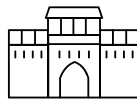
लखनऊ



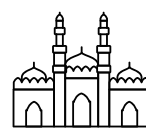
जयपुर



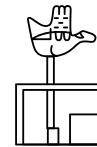
हैदराबाद



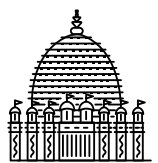
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी